

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 522  
जिसका उत्तर मंगलवार 25 जून, 2019 को दिया जाना है

**फेम इंडिया योजना**

522. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पर्यावरण-हितैषी ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने के लिए फेम इंडिया योजना को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या वाहन की लंबाई पर आधारित वर्गीकरण से वाहनों की भीड़भाड़ में कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड-उत्सर्जन आधारित वर्गीकरण समग्र पर्यावरण और हरीतिमा के अनुकूल होगा और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करेगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री  
(श्री अरविंद गणपत सावंत)**

**(क) और (ख):** भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर और उद्योग एवं उद्योग संघों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करने के बाद, भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया योजना के चरण-II को अंतिम रूप दिया और तदनुसार दिनांक 08 मार्च, 2019 को इसे अधिसूचित किया जो ₹10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। यह चरण मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर केन्द्रित होगा, और सब्सिडी के माध्यम से 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की सहायता करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच अनेक उत्सुकताओं का समाधान करने के लिए चुनिन्दा शहरों में और मुख्य राजमार्गों पर चार्जिंग अवसंरचना के सृजन की सहायता की जाएगी।

**(ग) से (घ):** जी, हां। वाहनों पर जीएसटी का निर्णय लेने के लिए वाहनों का लम्बाई आधारित वर्गीकरण लागू है। वाहन संबंधी भीड़भाड़ में कमी करने की दृष्टि से छोटे वाहनों के लिए कम जीएसटी और बड़े वाहनों पर अधिक जीएसटी लागू है।

इसी प्रकार, सीएएफई मानकों के माध्यम से कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा रहा है जिसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जनों की कटौती में सरकार के समग्र विजन के अनुसार उनके द्वारा विनिर्मित प्रत्येक मॉडल पर कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए कंपनियों को निदेश दिए जा रहे हैं।